भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 578
उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम

578. **श्री शफी परम्बिल:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्यम सहायता मंच के माध्यम से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए औपचारिक दायरे में लाए गए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उन अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) की संख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं जिन्हें इस मंच से जुड़ने के पश्चात प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ मिला है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख) : दिनांक 25 नवंबर, 2024 तक, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर पंजीकरण के माध्यम से प्राथमिकता वाले क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु औपचारिक दायरे में लाए गए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है। एमएसएमई मंत्रालय की दिनांक 20 मार्च, 2023 की राजपत्र अधिसूचना स.आ.1296(ई) के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए आईएमई को यूएपी पर जारी किए गए प्रमाण-पत्र को उद्यम पंजीकरण प्रमाण-पत्र के समतुल्य माना जाएगा। भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ पाने वाले आईएमई का डेटा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 578, जिसका उत्तर दिनांक 28.11.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 20.11.2024 तक उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम	यूएपी पर पंजीकृत आईएमई की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,773
2	आंध्रप्रदेश	14,19,825
3	अरुणाचल प्रदेश	10,697
4	असम	2,92,346
5	बिहार	17,76,666
6	चंडीगढ़	12,738
7	छत्तीसगढ	5,11,834
8	दिल्ली	2,92,624
9	गोवा	35,279
10	गुजरात	10,83,688
11	हरियाणा	4,16,896
12	हिमाचल प्रदेश	52,013
13	जम्मू और कश्मीर	2,00,632
14	झारखंड	6,15,918
15	कर्नाटक	18,00,398
16	केरल	5,54,202
17	लद्दाख	4,610
18	लक्षद्वीप	810
19	मध्य प्रदेश	20,27,625
20	महाराष्ट्र	22,33,854
21	मणिपुर	38,958
22	मेघालय	8,536
23	मिजोरम	11,887
24	नागालैंड	20,522
25	ओडिशा	8,18,763
26	पुडुचेरी	33,994
27	पंजाब	4,03,402
28	राजस्थान	9,65,620
29	सिक्किम	9,023
30	तमिलनाडु	13,38,907
31	तेलंगाना	9,63,845
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	5,179
33	त्रिपुरा	1,73,205
34	उत्तराखंड	1,57,523
35	उत्तर प्रदेश	29,42,337
36	पश्चिम बंगाल	26,54,458
कुल		**2,38,91,587**